(c) whether the Modis had put forward the proposal to set up a plant in Srinagar to manufacture 18 lakh spare parts and assemble 10 lakh watches per annum;

(d) if so, whether in view of the rejection by the HMT, the Union Government has permitted the Modis to set up the same; and

(e) if not, what are the main reasons for not allowing them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Yes, Sir.

(d) and (e). A Task Force was constituted by the Government of India in June, 1979 to formulate a policy for watch manufacture. The report of the Committee is being examined by the Government. M/s. Modi Rubber Ltd. have, in the meantime, substantially revised their scheme for manufacture of watches. This will be considered in the light of the decision taken on the report of the Task Force.

Refusal of permission for setting up of Battery manufacturing and watch making Units in J & K

6137. DR. FAROOQ ABDULLA:
SHRI GHULAM RASOOL KOCHACK:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Centre has refused permission to Union Carbide and Modis to set up a Battery manufacturing plant and a watch making unit respectively in Kashmir;

(b) if so, what are the main reasons for the same;

(c) whether proposal of Hindustan Lever to set up nutrient plant in Jammu has been permitted; and

(d) if so, what are its main features?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) and (b). The application from M/s. Union Carbide India Ltd. for the grant of an industrial licence for the manufacture of dry batteries was rejected as the applicant company was already dominant in the manufacture of dry batteries and no additional capacity was necessary for the item.

The application of M/s. Modi Rubber Ltd. for foreign collaboration for establishing a project to manufacture wrist watches in Srinagar has been closed pending finalisation of the policy on wrist watches.

(c) No final decision has been taken as yet.

(d) Does not arise.

भारतीय सेना में "बैटमैन सिस्टम"

6138. **श्री राम विलास पासवान :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना में "बैटमैन सिस्टम" अब भी प्रचलित है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह पद्धति नौसेना और वायु सेना में भी प्रचलित है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हो० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग). युद्ध स्थापनाओं के साथ कार्य कर रही विरचनाओं तथा यूनिटों के अफसरों और जूनियर कमीशन अफसरों को इस समय निम्नलिखित दर पर थलसेना में बैटमैन (अर्दली) प्राधिकृत है :—

(क) प्रत्येक सूबेदार मेजर, फील्ड अफसर और उस से ऊपर के अफसर को एक ।

(ख) कैप्टन और उनसे नीचे के रैंक के प्रत्येक दो अफसरों और सूबेदारों तथा नायक सूबेदारों के लिए एक ।

2. अर्दली (बैटमैन) योधी सैनिक है । उन्हें अन्य सभी सिपाहियों की तरह सामान्य प्रशिक्षण दिया जाता है और वे संक्रियाओं, अभ्यासों तथा प्रशिक्षण के दौरान अफसरों तथा जूनियर कमीशन अफसरों की सहायता करते हैं । इनकी सेवाओं का उपयोग मुख्यत बायरलेस सेट ले जाने, संदेश तथा डाक ले जाने और अफसरों तथा जूनियर कमीशन अफसरों के वैयक्तिक कार्य करने के लिए

किया जाता है जबकि ये अफसर सामान्यतया अग्रिम पंक्ति पर युद्ध संचालन संबंधी कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अफसर तथा जूनियर कमीशन अफसर उसे "सशस्त्र साथी (कामरेड इन आर्मस)" समझते हैं और उसका वही दर्जा होता है जो किसी अन्य सिपाही का।

3. अर्दली (बैटमैन) की व्यवस्था संचालन की दृष्टि से सेना में होनी आवश्यक है और अधिकांश विदेशी सेनाओं में भी ऐसी व्यवस्था है।

4. वायु सेना तथा नौसैना में बैटमैन नहीं है क्योंकि वहां इस वर्ग के कार्मिकों की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है।

परीक्षा-पूर्व केन्द्र, करोल बाग में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों के लिए हिन्दी टाइप की मशीनें

6139. **श्री केशव राव पारधी :**
श्री नन्द किशोर शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के लिए चलाये जा रहे परीक्षा-पूर्व केन्द्र करोल बाग में हिन्दी टाइप की मशीनें नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर टाइप मशीनें उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आशुलिपि परीक्षा के लिए टाइप राइटिन्ग परीक्षण आवश्यक है ; और

(घ) यदि हां, तो वहां पर टाइप मशीनें उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। केन्द्र में हिन्दी टाइप राईटर उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) केन्द्र में हिन्दी टाइप मशीनें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षुओं को आशुलिपिक परीक्षा के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।

Rehabilitation of Refugees in Assam and Tripura

6140. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether in view of the political situation prevailing in Assam and Tripura, the burden of rehabilitation has gone up very high;

(b) whether the Central Government propose to assist these State Governments to cope with the problem; and

(c) if so, the quantum of assistance proposed for these two States separately and the criteria for allocation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (c). The Central Government recently gave a ways and means advance of Rs. 2 crores to the Tripura Government, at the request of that Government, to enable it to finance expenditure on relief and rehabilitation of persons affected by the recent civil disorder. No such request was made by the Assam Government.

Normally it is for the State Governments to finance all expenditure in connection with disturbances resulting in the loss of property etc. However, having regard to the situation which Tripura had to face and the fact that its resources are too meagre to meet the additional financial burden on rehabilitation measures without seriously impairing its development plan, the Central Government may consider ways and means to provide such assistance as the situation warrants.

Quality control of Power Generation Equipment

6141. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what steps are being taken by Government to ensure quality control of power generation equipment being